शनिवार, 14 फरवरी, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

रियान पराग राजस्थान के नए कप्तान

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

बॉक्स ऑफ़िस ओ रोमियो की धमकेदार शूरुआत

Page-05

'बांग्लादेश फर्स्ट' के साथ नई पारी की शुरुआत,

क्षेत्रीय कूटनीति पर टिकी निगाहें

अंतर्राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

ढाका: बांग्लादेश में सत्ता संभालने जा रहे नए नेतृत्व ने 'बांग्लादेश फर्स्ट' नीति को अपनी सरकार का मूल मंत्र बताया है। शपथ ग्रहण से पहले दिए गए संकेतों में स्पष्ट किया गया है कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय हित, आर्थिक आत्मनिर्भरता और संप्रभु निर्णय-प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह सोच काफी हद तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति से प्रेरित दिखाई देती है, जिसमें घरेलू हितों को वैश्विक प्रतिबद्धताओं पर प्राथमिकता दी गई थी।नए नेतृत्व ने कहा है कि उनकी सरकार का ध्यान स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और विदेशी निर्भरता कम करने पर रहेगा। इसके तहत व्यापार समझौतों की समीक्षा, रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने और लघु-मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन नीतियों को संतुलित ढंग से लागू किया गया तो देश की विनिर्माण क्षमता और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है।हालांकि, 'बांग्लादेश फर्स्ट' नीति के संभावित प्रभावों को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। दक्षिण एशिया में व्यापार, ऊर्जा सहयोग और सीमा पार संपर्क परियोजनाओं पर इसका असर पड़ सकता है। विश्लेषकों के अनुसार, यदि सरकार आयात पर सख्ती या संरक्षणवादी रुख अपनाती है, तो पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, समर्थकों का तर्क है कि मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था ही दीर्घकालिक क्षेत्रीय साझेदारी का आधार बन सकती है।राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता भी इस नीति का अहम हिस्सा बताई जा रही है। नई सरकार रक्षा सहयोग और विदेश नीति में संतुलन बनाते हुए बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाने की बात कर रही है। कूटनीतिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि बांग्लादेश वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन साधने की कोशिश करेगा, ताकि आर्थिक अवसरों का लाभ उठाते हुए अपनी संप्रभुता से समझौता न करना पड़े। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि 'बांग्लादेश फर्स्ट' नीति किस रूप में लागू होती है और इसका घरेलू राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय समीकरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इतना तय है कि नई सरकार राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर अपनी अलग पहचान बनाने की तैयारी में है।

ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक हार

AUS vs ZIM: टी20 वर्ल्डकप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए. टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया 146 रन पर सिमट गई. जिम्बाब्वे ने इस मैच को 23 रन से अपने नाम कर लिया.

राजधानी में राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव:
परिवार की बुजुर्ग महिला बनेगी कार्ड की मुखिया

दिल्ली, टीवी भारतवर्ष

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 'दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026' के तहत अब राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में परिवार के मुखिया की परिभाषा को संशोधित किया गया है। हाल ही में अधिसूचित इन नियमों का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है।नए प्रावधानों के अनुसार, राशन कार्ड जारी करते समय परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और परिवार में उनकी भूमिका को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में उठाया गया है।हालांकि, नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि परिवार में केवल एक ही महिला सदस्य है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य को मुखिया के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, संशोधित नियमों में सालाना आय की सीमा और एक परिवार को जारी किए जाने वाले

राशन कार्ड की संख्या से जुड़े मानकों में भी बदलाव किया गया है। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होगी और अपात्र लोगों को सूची से बाहर किया जा सकेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए नियमों के लागू होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी।

बिकवाली के दबाव में धड़ाम हुआ बाजार,
निवेशकों की संपत्ति में भारी गिरावट

मुंबई, टीवी भारतवर्ष

सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। व्यापक बिकवाली के चलते सेंसेक्स 1048 अंकों की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 25,500 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया। बाजार में आई इस तेज गिरावट से निवेशकों को बड़ा झटका लगा और अरबों रुपये की पूंजी डूब गई।कारोबार की शुरुआत से ही बाजार पर दबाव देखने को मिला। आईटी, बैंकिंग, ऑटो और मेटल सेक्टर के शेयरों में तेज बिकवाली ने प्रमुख सूचकांकों को नीचे खींचा। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेत, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और घरेलू स्तर पर मुनाफावसूली को गिरावट की प्रमुख वजह माना जा रहा है।विश्लेषकों के अनुसार, हालिया तेजी के बाद बाजार ऊंचे स्तरों पर पहुंच गया था, जिसके चलते निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और ब्याज दरों को लेकर बनी चिंताओं ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया।

एशियाई और अमेरिकी बाजारों में कमजोरी का असर भी घरेलू बाजार पर देखने को मिला। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में सबसे अधिक दबाव रहा, जिससे सेंसेक्स में बड़ी गिरावट आई। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी बिकवाली का माहौल रहा, हालांकि कुछ रक्षात्मक क्षेत्रों जैसे एफएमसीजी और फार्मा में सीमित खरीदारी देखी गई।विशेषज्ञों का कहना है कि निकट भविष्य में बाजार की दिशा वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों के रुख और प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी।

'उरीमाई थोगाई' पर सीएम स्टालिन का दोटूक संदेश:
महिलाओं से किया वादा हर हाल में निभेगा

तमिलनाडु, टीवी भारतवर्ष

तमिलनाडु में महिलाओं के खातों में 'उरीमाई थोगाई' (अधिकार अनुदान) की राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर होने के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यह राज्य की महिलाओं से किया गया उनका वादा था, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "कोई भी रुकावट डाले, मैं पीछे नहीं हटूंगा।"राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आर्थिक सहायता भेजी गई है। सरकार का दावा है कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और परिवार की आय में स्थिरता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि 'उरीमाई थोगाई' केवल एक वित्तीय सहायता योजना नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ा संकल्प है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के सिद्धांतों पर काम कर रही है और महिलाओं की भागीदारी के बिना राज्य का विकास अधूरा है।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लाखों महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिला है। अधिकारियों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई है और पात्रता मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की गई है।विपक्ष की ओर से योजना को लेकर उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित की योजनाओं को राजनीतिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी ऐसी योजनाएं जारी रहेंगी।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह योजना राज्य की सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है, खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के जीवन स्तर पर। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए व्यापक स्तर पर डेटा सत्यापन और बैंक खातों की जांच की गई, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि या दोहराव की संभावना को समाप्त किया जा सके। जिन लाभार्थियों के खातों में तकनीकी कारणों से राशि नहीं पहुंच पाई, उनके लिए विशेष शिविर और हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का कहना है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले महीनों में योजना की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार इसके दायरे या लाभ राशि में संशोधन पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीनी स्तर पर योजना के प्रभाव का आकलन किया जाए और लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लिया जाए।

बांग्लादेश चुनाव में BNP की ऐतिहासिक जीत,

पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई

बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर दो-तिहाई बहुमत प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए भारत के समर्थन और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। बीएनपी नेताओं ने भी भारत के साथ सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की बात कही।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

दक्षिण एशियाई राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में Bangladesh Nationalist Party (बीएनपी) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही देश में तथाकथित 'रहमान युग' की वापसी की चर्चा तेज हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बीएनपी के नेता तारिक रहमान को इस 'अहम' जीत पर बधाई दी और भारत-बांग्लादेश संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि बीएनपी की यह जीत बांग्लादेश की जनता के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम दर्शाता है कि देश के लोग तारिक रहमान के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह उनके साथ मिलकर काम करने और दोनों देशों के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तारिक रहमान को टैग करते हुए लिखा कि भारत हमेशा "डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और इनक्लूसिव" बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में संसदीय चुनावों में बीएनपी को अहम जीत दिलाने के लिए मैं मिस्टर तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपकी लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है। मैं हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।" हालांकि चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक नतीजों की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बीएनपी ने 300 सदस्यीय संसद में पहले ही दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी 212 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जिससे उसकी स्थिति बेहद मजबूत हो गई है। दूसरी ओर, Jamaat-e-Islami के नेतृत्व वाले 11-पार्टी गठबंधन को चुनावों में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इस गठबंधन को लगभग 70 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है और आने वाले समय में नीति-निर्माण की दिशा पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। बीएनपी की जीत के बाद पार्टी नेताओं ने भी भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने की बात कही है। बीएनपी नेता ज़ेबा अमीना खान ने कहा कि बांग्लादेश और भारत पड़ोसी देश हैं और दोनों के संबंध दोस्ताना बने रहने चाहिए। उन्होंने कहा, "हम पड़ोसी हैं, हम दोस्त हैं, और हमें दोस्त बने रहना चाहिए। हमारा बॉर्डर बहुत बड़ा है। जो भारत के लिए सुरक्षा जोखिम है, वह हमारे लिए भी सुरक्षा जोखिम है।" उन्होंने आगे कहा कि सीमा क्षेत्रों में मौजूद छोटे-मोटे मुद्दों को आपसी सहयोग और संवाद के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, ताकि दोनों देश मिलकर शांति और स्थिरता बनाए रख सकें। ज़ेबा अमीना खान ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश को भारत से कोई दिक्कत नहीं है और दोनों देशों को लोगों के हित में मिलकर काम करना चाहिए।

बीएनपी की इस जीत को बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति के साथ-साथ क्षेत्रीय समीकरणों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और कनेक्टिविटी जैसे कई अहम मुद्दे हैं, जिन पर दोनों देशों के बीच लगातार सहयोग रहा है। ऐसे में नई राजनीतिक परिस्थितियों में इन संबंधों की दिशा पर विशेष ध्यान रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से समय पर दी गई बधाई और सहयोग का संदेश यह दर्शाता है कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और पारस्परिक विकास को प्राथमिकता देता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि नई सरकार अपने चुनावी वादों को किस प्रकार लागू करती है और भारत-बांग्लादेश संबंधों को किस दिशा में आगे बढ़ाती है।

अगले पांच वर्षों में 50 नए हवाई अड्डे बनाएगा भारत

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने शुक्रवार को कहा कि भारत का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 50 और नए हवाई अड्डे बनाने का है। उन्होंने कहा कि इससे देश के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए बड़े अवसर उत्पन्न होंगे। मंत्री के अनुसार, हवाई अड्डे किसी भी क्षेत्र के रियल एस्टेट विकास की "आधार" होते हैं और इनके आसपास बुनियादी ढांचे के विस्तार से संपत्ति बाजार को सीधा लाभ मिलता है।नायडू ने बताया कि वह विमानन सुरक्षा से समझौता किए बिना हवाई अड्डों के आसपास इमारतों की ऊंचाई से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है, वर्तमान में देश में 165 चालू हवाई अड्डे हैं और औसतन हर 33 दिन में एक नया हवाई अड्डा या नया टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। यह आंकड़ा देश के बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार को दर्शाता है।मंत्री ने यह बातें रियल एस्टेट उद्योग निकाय 'नारेडको' द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 'राष्ट्रीय शहरी एवं रियल एस्टेट विकास सम्मेलन 2026' में कहीं। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों के विकास से आसपास के क्षेत्रों में आवास, वाणिज्यिक परियोजनाओं और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। देश के रियल एस्टेट क्षेत्र की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए नायडू ने कहा कि 2030 तक इस क्षेत्र का आकार लगभग 1000 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2047 तक बढ़कर 5000 से 7000 अरब डॉलर के बीच हो सकता है। उन्होंने जोर दिया कि रियल एस्टेट विकास में केवल जीवन स्तर ही नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजी से शहरीकरण के इस दौर में संतुलित, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण विकास ही देश की दीर्घकालिक प्रगति का आधार बनेगा।

अगले हफ्ते दिल्ली में 40-50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं,

पीएम मोदी की कूटनीति पर होगी वैश्विक नजर

भारत की रक्षा में नई क्रांति:

एयर-शिप बेस्ड HAPS को मंजूरी

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए एयर-शिप बेस्ड हाई-एल्टीट्यूड प्सूडो सैटेलाइट (AS-HAPS) खरीदने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला भारत की रक्षा रणनीति में आए बड़े बदलाव का संकेत है, जिसमें पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ निगरानी और खुफिया क्षमता को युद्ध जीतने का अहम हथियार माना जा रहा है।करीब 3.60 लाख करोड़ रुपये के विशाल पूंजीगत रक्षा पैकेज का हिस्सा, AS-HAPS उन तकनीकों में शामिल है जो दुश्मन की गतिविधियों पर निरंतर नजर रख सकती हैं। राफेल विमान और मिसाइलें भले ही दुश्मन पर प्रहार करें, लेकिन HAPS दुश्मन की हर हरकत पर निगाह रखकर उसे छुपने की गुंजाइश ही नहीं देता।HAPS एक सौर ऊर्जा से चलने वाला मानव रहित विमान है, जो धरती से लगभग 18–20 किलोमीटर की ऊंचाई पर महीनों तक टिक सकता है। यह पारंपरिक उपग्रहों के मुकाबले सस्ता और नियंत्रण में आसान है, जबकि ड्रोनों के मुकाबले लंबे समय तक और बड़े क्षेत्र में निगरानी प्रदान करता है। इसी कारण इसे "प्सूडो सैटेलाइट" कहा जाता है।इस आवश्यकता की पहचान 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान हुई थी, जब भारत को अपनी लंबी और जटिल सीमाओं पर 24 घंटे निगरानी की कमी महसूस हुई। HAPS रियल-टाइम तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी और संचार सहायता प्रदान कर सकता है। यह दुश्मन के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव भी पैदा करता है।भारत

इस तकनीक में सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनने की दिशा में भी बढ़ रहा है। बेंगलुरु की राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला ने हल्के प्रोटोटाइप विकसित कर परीक्षण सफल किए हैं। निजी क्षेत्र के डीप-टेक स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगर यह पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हुआ, तो भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि भविष्य में HAPS निर्यातक भी बन सकता है।HAPS केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। यह आपदा प्रबंधन, दूरदराज क्षेत्रों में संचार, 5G नेटवर्क, कृषि निगरानी और पर्यावरण अध्ययन जैसे क्षेत्रों में भी क्रांति ला सकता है।अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया पहले ही इस तकनीक में आगे हैं। भारत का इसमें शामिल होना अब अनिवार्य हो गया है। यह कदम यह स्पष्ट करता है कि आज की दुनिया में जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, जानकारी से जीती जाती है। भारत अब आसमान से नजर रखेगा और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को और सुदृढ़ बनाएगा।

चीनी जहाज को जापान ने दबोचा, भारी एक्शन

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अब जापान भी चीन के खिलाफ एक्शन लेने के मूड में है। तभी तो साल 2022 के बाद अब जापान ने कुछ ऐसा किया है जिससे चीन को मिर्ची लगनी तय है। जापानी अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिम जापान के नागासाकी के पास अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक चीनी मछली पकड़ने वाले नाव को जब्त कर लिया। उसके कप्तान को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि नाव ने जापानी निरीक्षण टीम के आदेशों की अनदेखी कर भागने की कोशिश की। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान और चीन के बीच पहले से ही एक बड़ा कूटनीतिक विवाद चल रहा है। जापान की फिशरी एजेंसी ने इस बयान को जारी करते हुए बताया कि 12 फरवरी की दोपहर के आसपास नागासाकी प्रीफेक्चर के गोतो द्वीप समूह के पास मेशिमा द्वीप से लगभग 89.4 नॉटिकल मील यानी कि करीब 165 कि.मी. दक्षिण पश्चिम में स्थित जापान की ईजेड में चीनी नाव क्यू ओंग डोंग यू 111998 को देखा गया। यह एक ट्रोलर प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव थी जिसमें जाले लगे हुए थे। फिश एजेंसी के पेट्रोल जहाज होकआ मारो ने नाव को रोकने और बोट पर निरीक्षण की अनुमति देने का आदेश दिया। लेकिन कप्तान ने आदेश की अवहेलना की और नाव भगाने लगा। इसके बाद जापानी अधिकारियों ने नाव को जब्त कर लिया और उसके 47 वर्षीय चीनी कप्तान को भी गिरफ्तार किया गया। नाव पर कुल 11 चालक दल के सदस्य थे जिनमें से कप्तान को हिरासत में लिया गया। बाकी सदस्यों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मीनारू केरा ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में इस घटना की पुष्टि की है और इस पर बयान भी दिया है। सुस सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब से ताइवान के मामले में जापान और चीन की टकराहट बढ़ी है। जापान ने वापस से परमाणु कार्यक्रम की तरफ कदम उठाने पर जोर दिया है। उसके बाद से ही यह तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साल 2022 के बाद पहली बार जापान ने चीनी मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त कर लिया। हाल के वर्षों में जापान ने दक्षिण कोरिया और ताइवान की नाव को भी इसी तरह जब्त किया है।

दिल्ली पुलिस की पेंगुइन इंडिया प्रतिनिधियों से पूछताछ, साजिश के एंगल पर जांच तेज

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे के बहुप्रतीक्षित और अब तक अप्रकाशित संस्मरण के कथित लीक होने का मामला अब कानूनी रूप ले चुका है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रतिनिधियों से पूछताछ की है। जांच का मुख्य बिंदु यह है कि क्या पुस्तक के संवेदनशील अंशों को सार्वजनिक करने से पहले रक्षा मंत्रालय की अनिवार्य स्वीकृति को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया।सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने इससे पहले प्रकाशक को लगभग 15 प्रश्नों का नोटिस भेजा था। इन सवालों में पांडुलिपि की स्थिति, प्रकाशन प्रक्रिया और आवश्यक सरकारी मंजूरी से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। बुधवार को पुलिस टीम ने गुरुग्राम स्थित संबंधित कार्यालय का दौरा कर प्रारंभिक जानकारी एकत्र की।बृहस्पतिवार को कंपनी के प्रतिनिधियों को औपचारिक रूप से पूछताछ के लिए बुलाया गया। बताया गया है कि उन्होंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, जबकि शेष सवालों के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राप्त जवाबों का विश्लेषण किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर कंपनी प्रबंधन तथा प्रकाशन से जुड़े अन्य अधिकारियों से भी आगे पूछताछ की जा सकती है।जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि क्या पुस्तक में ऐसे अंश शामिल थे जिनके प्रकाशन से पूर्व रक्षा मंत्रालय की अनुमति आवश्यक थी। यदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया पाया गया, तो मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।विवाद के बीच पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए बयान जारी किया है कि संबंधित पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। कंपनी ने कहा है कि उसकी ओर से पुस्तक की कोई भी प्रति—चाहे मुद्रित हो या डिजिटल—न तो जारी की गई है, न वितरित की गई है और न ही बेची गई है।फिलहाल मामला जांच के अधीन है और पुलिस आगे की कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों और जवाबों के आधार पर तय करेगी। यह प्रकरण रक्षा से जुड़े दस्तावेजों की गोपनीयता और प्रकाशन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है।

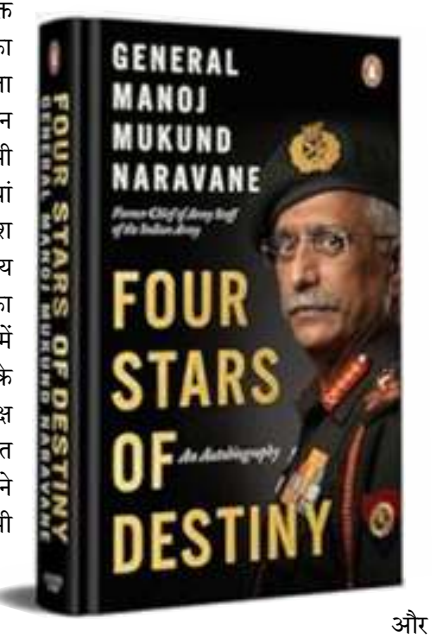

संपादक की कलम से

बांग्लादेश में चुनाव हर बार देश की राजनीतिक दिशा और लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का आईना साबित होते हैं। आगामी चुनाव भी कोई अपवाद नहीं है। इस बार की लड़ाई केवल सत्ता पर कब्ज़ा करने की नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों, सार्वजनिक भरोसे और विकास की दिशा को तय करने की है।पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में कई प्रगति की है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, विभाजन और विरोधी दलों के बीच टकराव ने अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुनौती दी है। ऐसे में चुनाव केवल मतदाताओं के अधिकार का उपयोग नहीं, बल्कि उनके कर्तव्य और जिम्मेदारी का परीक्षण भी है।लोकतंत्र का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि जनता अपनी आवाज़ के माध्यम से शासन का मार्गदर्शन करती है। इसलिए, हर नागरिक को अपने मत का प्रयोग सोच-समझकर करना चाहिए। चुनाव केवल मतदान तक सीमित नहीं होना चाहिए; यह उम्मीदवारों की योग्यता, उनके एजेंडा, विकास योजनाओं और न्यायप्रियता का मूल्यांकन करने का अवसर भी है।इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। हिंसा, भय और धमकियों से लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। साथ ही, मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने में सहायक होते हैं।बांग्लादेश का भविष्य उसकी जनता के हाथों में है। यह चुनाव न केवल सरकार बदलने का अवसर है, बल्कि यह तय करने का भी समय है कि लोकतंत्र के मूल्यों, विकास और सामाजिक न्याय को किस दिशा में ले जाना है।इसलिए, हर नागरिक को मतदान में भाग लेकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र की यह प्रक्रिया सही मायनों में सफल और पारदर्शी हो। चुनाव का परिणाम केवल राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि पूरी राष्ट्र की दिशा तय करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सेवा तीर्थ' कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया

PMO और राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय अब एक ही परिसर में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 'सेवा तीर्थ' कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। अब PMO, कैबिनेट सचिवालय और NSCS एक ही परिसर में शिफ्ट होंगे। प्रधानमंत्री ने योजनाओं पर हस्ताक्षर किए, महिला, युवा और कमजोर वर्गों के लाभ सुनिश्चित किए। कॉम्प्लेक्स आधुनिक सुविधाओं से लैस है और प्रशासनिक कामकाज केंद्रीकृत करेगा।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 'सेवा तीर्थ' कॉम्प्लेक्स का औपचारिक उद्घाटन किया। इस कॉम्प्लेक्स में अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय (NSCS) और कैबिनेट सचिवालय का संचालन होगा। उद्घाटन के साथ ही PMO आज से रायसीना हिल स्थित साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा।उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने नए कॉम्प्लेक्स में लगी 'सेवा तीर्थ' की पट्टिका का अनावरण किया। परिसर की दीवार पर देवनागरी लिपि में 'सेवा तीर्थ' लिखा गया है। इसके नीचे 'नागरिक देवो भव' (नागरिक भगवान के समान हैं) का मंत्र भी अंकित है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े अहम फैसलों की फाइलों पर भी हस्ताक्षर किए।न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ से एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा, वे पुराने PM ऑफिस में केंद्रीय कैबिनेट की विशेष बैठक भी करेंगे, जो शुक्रवार शाम 4 बजे आयोजित होगी। यह ब्रिटिश काल की सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय 1947 से स्थित था और यह इमारत करीब 78 वर्षों से देश की सत्ता का केंद्र रही है। 2014 से मोदी सरकार ने ब्रिटिश शासनकाल के प्रतीकों से दूर जाने के लिए लगातार कदम उठाए हैं।नई व्यवस्था के तहत, सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में तीन इमारतें हैं – सेवा तीर्थ-1, सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3। सेवा तीर्थ-1 में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) स्थित है। सेवा तीर्थ-2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ-3 में NSCS और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का कार्यालय है। ये सभी कार्यालय पहले अलग-अलग जगहों पर थे। कैबिनेट सचिवालय सितंबर 2025 में ही सेवा तीर्थ-2 में शिफ्ट हो चुका है, जबकि आज PMO और NSCS भी यहां स्थानांतरित हो गए हैं।प्रधानमंत्री ने PM राहत योजना से जुड़ी फाइलों पर हस्ताक्षर किए। इस योजना के तहत एक्सीडेंट पीड़ितों को 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, ताकि उनके इलाज में कोई देरी न हो। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी योजना के तहत लक्ष्यों को दोगुना करते हुए 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने का निर्णय लिया।कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के आवंटन को 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी। इसके साथ ही, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष की भी मंजूरी दी गई।सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का कुल क्षेत्रफल करीब 2.26 लाख वर्ग फीट (लगभग 5 एकड़) है। इसे एल एंड टी कंपनी ने 1189 करोड़ में तैयार किया है। सेवा तीर्थ का मतलब है 'सेवा का स्थान'। पहले इसका नाम 'एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' रखा गया था, लेकिन 2 दिसंबर 2025 को इसे सेवा तीर्थ नाम दिया गया। यह नई दिल्ली में दारा शिकोह रोड पर स्थित है।नई सुविधा में प्रधानमंत्री के नए आवास का निर्माण भी जारी है। तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित वर्तमान आवास से नए आवास में शिफ्ट होंगे। हालांकि, शिफ्टिंग की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में आज कर्तव्य भवन-1 और 2 का भी उद्घाटन करेंगे। इन भवनों में मंत्रालयों के नए कार्यालय होंगे, जो पहले नॉर्थ ब्लॉक में थे। इस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रशासनिक कामकाज को केंद्रीकृत और आधुनिक तकनीक से लैस करने का उद्देश्य है।प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के मौके पर कहा कि सेवा तीर्थ एक ऐसा स्थल है, जहां सभी निर्णय और कामकाज सीधे जनता की सेवा के उद्देश्य से होंगे। उन्होंने कहा कि 'नागरिक देवो भव' का मंत्र सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा और सरकार की प्राथमिकता हमेशा जनता की भलाई और सुविधा रहेगी।इस प्रकार सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भारतीय प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ सभी महत्वपूर्ण कार्यालय एक ही परिसर में केंद्रीकृत हो गए हैं।

हंगामे के बीच बजट सत्र का पहला चरण समाप्त, सदन 9 मार्च तक स्थगित

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के संस्मरण से जुड़े विवाद पर कई दिनों तक चले तीखे राजनीतिक वाद-विवाद के बीच शुक्रवार को संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया। विवाद संसद के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भी चर्चा का विषय बना रहा।लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। दोनों सदन अब तीन सप्ताह के अवकाश पर चले गए हैं और लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही 9 मार्च से फिर शुरू होगी।बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन के साथ शुरू हुआ था। मध्यावधि अवकाश के दौरान स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान मांगों की जांच करेंगी। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक टिप्पणी पर हंगामा हुआ, जिससे चर्चा बाधित हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे सके। हालांकि इस सप्ताह आम बजट पर चर्चा हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया।विपक्ष ने राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न देने और आठ सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव सत्र के दूसरे चरण में सूचीबद्ध हो सकता है।राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। आम बजट 2026-27 पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने उत्तर दिया। उच्च सदन में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक पारित किया गया।सांसद संजय सिंह ने सेना भर्ती प्रक्रिया और सैनिकों की तैनाती का मुद्दा उठाया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कोडीन आधारित कफ सिरप से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। जम्मू-कश्मीर के छात्रों के प्रवेश मुद्दे को भी राज्यसभा में उठाया गया।

राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्र का पलटवार,

कहा– किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा इस समझौते पर सवाल उठाए जाने के बाद, केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान- ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों मंत्रियों ने राहुल गांधी पर "झूठ फैलाने" और किसानों को "गुमराह" करने का कड़ा आरोप लगाया है। दोनों मंत्रियों ने दावा किया कि इस समझौते के तहत किसानों के हितों की ''पूरी तरह से रक्षा'' की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किए गए वीडियो संदेशों में गांधी को ऐसे ''आदतन झूठे'' व्यक्ति करार दिया जो नहीं चाहते कि किसान सशक्त हों। मंत्रियों ने ये टिप्पणियां गांधी द्वारा 'एक्स' पर साझा किए गए उस वीडियो संदेश के बाद कीं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर ''किसान-विरोधी'' होने और भारत एवं अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के जरिये देश को ''बेचने'' का आरोप लगाया है। गोयल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, ''आज जारी वीडियो में उन्होंने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और निराधार आरोप लगाए हैं। वह अपने फर्जी विमर्श के जरिये हमारे किसानों को गुमराह कर रहे हैं और हमारे अन्नदाता को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारी मातृभूमि की कभी परवाह नहीं की और हम उनसे भारत के मजबूत एवं समृद्ध भविष्य के लिए काम करने की कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते।'' गोयल ने कहा कि गेहूं, चावल, मोटा अनाज, सोयाबीन, मक्का, आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (जीएम) खाद्य उत्पाद, मसाले और आलू सहित प्रमुख फसलों को ''पूरी तरह संरक्षित'' किया गया है। उन्होंने कहा, ''हमने सेब सहित प्रमुख फलों का उत्पादन करने वाले किसानों के हितों को भी पूरी तरह संरक्षित किया है। भारत के दरवाजे दुग्ध उत्पादों या पोल्ट्री के लिए नहीं खोले गए हैं।'' गोयल ने कहा कि सच्चाई यह है कि व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप बासमती चावल, फलों, मसालों, चाय और समुद्री उत्पादों सहित कई उत्पादों को नये बाजार मिलेंगे और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की आय बढ़ेगी। मंत्री ने कहा, ''हमने कपास वस्त्र निर्यात के लिए बड़े बाजार खोले हैं, जिससे कपास की मांग कई गुना बढ़ेगी और हमारे

कपास किसानों को लाभ होगा।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं और उन्होंने उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी फैसले किए हैं। गोयल ने कहा, ''अमेरिका के साथ हालिया व्यापार समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है और इन्हें पूरी तरह संरक्षित किया गया है।'' कृषि मंत्री चौहान ने भी गांधी के दावों को ''निराधार'' बताया।

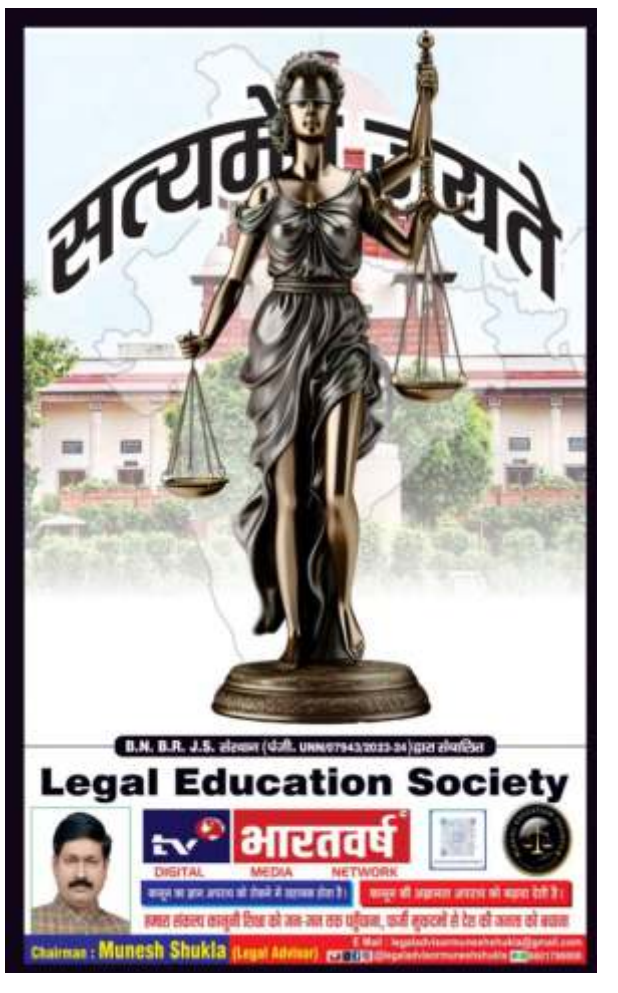

देश में IAS-IPS के 2500 से अधिक पद खाली

UPSC पर बढ़ी चर्चा

देश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सिविल सेवाओं में अधिकारियों की कमी ने प्रशासनिक प्रणाली पर चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने संसद में बताया कि भारत की तीन प्रमुख सेवाओं—आईएएस (Indian Administrative Service), आईपीएस (Indian Police Service) और आईएफओएस (Indian Forest Service)—में कुल 2,834 से अधिक पद वर्तमान में खाली हैं। इसमें सबसे अधिक खाली पद आईएएस में हैं, जहां 1,300 पद रिक्त हैं, इसके बाद आईपीएस में 505 और आईएफओएस में 1,029 पद खाली हैं। यह आंकड़ा 1 जनवरी, 2025 के अनुसार जारी किया गया है।सरकार के अनुसार, तीनों सेवाओं में कुल 15,169 स्वीकृत पद हैं, लेकिन इनमें से केवल 12,335 पदों पर अधिकारी तैनात हैं। यानी 2,834 पद खाली हैं, जो प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं।आईएएस में कुल स्वीकृत पद 6,877 हैं, जिनमें वर्तमान में केवल 5,577 अधिकारी ही कार्यरत हैं। वहीं, आईपीएस में 5,099 स्वीकृत पदों में 4,594 अधिकारी तैनात हैं। आईएफओएस में 3,193 पदों में से सिर्फ 2,164 अधिकारी ही सेवा दे रहे हैं।कैडर-वार आंकड़ों से पता चलता है

कि आईएएस में सबसे अधिक खाली पद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं। उत्तर प्रदेश में 652 स्वीकृत पदों में से केवल 571 अधिकारी ही तैनात हैं। मध्य प्रदेश में 459 पदों में 391 और महाराष्ट्र में 435 पदों में केवल 359 अधिकारी ही कार्यरत हैं।आईपीएस में भी राज्यों के बीच पदों और तैनात अधिकारियों में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्वीकृत पदों और तैनात अधिकारियों में अंतर प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर असर डाल सकता है।आईएफओएस (वन सेवा) सबसे अधिक प्रभावित सेवा है। 1,029 खाली पदों के साथ यह सेवा गंभीर रूप से रिक्त पाई गई है, जिससे वन संरक्षण और पर्यावरणीय नीतियों के क्रियान्वयन पर असर पड़ने की संभावना है।पिछले पांच वर्षों (2020–2024) में आरक्षित वर्ग उम्मीदवारों की सीधी भर्ती के आंकड़े भी सामने आए हैं। आईएएस में इस अवधि में 245 ओबीसी, 135 एससी और 67 एसटी उम्मीदवार नियुक्त हुए। आईपीएस में क्रमशः 255 ओबीसी, 141 एससी और 71 एसटी उम्मीदवार भर्ती किए गए। आईएफओएस में 231 ओबीसी, 95 एससी और 48 एसटी उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया।ये आंकड़े सांसद और सीपीआई-एम सदस्य जॉन ब्रिटास द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में सरकार ने साझा किए। अधिकारियों की इस कमी के कारण प्रशासनिक कार्यों, कानून-व्यवस्था और वन संरक्षण में दिक्कतें आने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द भर्ती और नियुक्तियों पर ध्यान न दिया गया, तो प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र पर दबाव और बढ़ सकता है।अंकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश में सिविल सेवाओं में रिक्त पद केवल संख्या का मुद्दा नहीं हैं, बल्कि यह प्रशासनिक क्षमता और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी सीधा असर डालते हैं।

"सहवाग ने जिम्बाब्वे की ऑस्ट्रेलिया पर जीत पर मजाकिया अंदाज में दिया 'डिनर का न्योता' वायरल

बिलकुल, यहाँ आपके दिए गए विवरण को अखबार की शैली में लगभग 350 शब्दों में पेश किया गया है:पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने जिम्बाब्वे की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत को लेकर मजाकिया अंदाज में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। सहवाग ने 1983 और 2007 के वर्ल्ड कप अभियानों का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि उन दोनों मौकों पर भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और अंत में भारत ने चैम्पियन का खिताब जीता था। अब 2026 में फिर जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, तो सहवाग ने इसे "लकी चार्म" बताते हुए डिनर देने की बात कह दी।सहवाग का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और फैन्स भी कमेंट सेक्शन में 1983 और 2007 की यादें ताजा कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे 'शुभ संकेत' बताते हुए उम्मीद जताई है कि इतिहास दोहराया जा सकता है। वहीं कुछ ने मजाकिया अंदाज में सवाल किया, "इतिहास खुद को दोहराएगा क्या?"सहवाग का यह हल्का-फुल्का कमेंट केवल मजाक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय क्रिकेट फैन्स के बीच उम्मीद और उत्साह भी बढ़ा गया है। 'We owe you dinner' वाले उनके कमेंट ने दर्शाया कि क्रिकेट जगत में परंपरा और पुराने रिकॉर्ड हमेशा चर्चा में रहते हैं।विशेष रूप से टी20 जैसे फास्ट-पेस फॉर्मेट में, जिम्बाब्वे की इस जीत ने साबित कर दिया कि मैदान पर नाम और प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि प्रदर्शन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर क्रिकेट की किसी भी फॉर्मेट में असंभव को संभव बनाने की क्षमता दिखाई है।सहवाग के पोस्ट और जिम्बाब्वे की जीत ने भारतीय फैन्स के बीच भी उत्सुकता और चर्चा को बढ़ा दिया है। क्रिकेट विश्लेषक मानते हैं कि यह जीत छोटे क्रिकेटing देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और दर्शाती है कि कोई भी टीम बड़ी चुनौती के लिए तैयार हो सकती है।इस प्रकार, सहवाग का मजाकिया कमेंट और जिम्बाब्वे की प्रदर्शन-प्रधान जीत ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और क्रिकेट प्रेमियों के बीच पुराने वर्ल्ड कप की यादें और नए उत्साह दोनों को ताजा कर दिया है।

एक और हार फेर देगी
ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी

अभिषेक शर्मा की फिटनेस पर सस्पेंस

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने ग्रुप-ए के मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ 93 रनों से शानदार जीत हासिल की थी। उस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अस्वस्थ होने के कारण खेल नहीं पाए थे। अभिषेक को पेट में संक्रमण के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि, अभी तक वे पूरी तरह फिट नहीं हैं।अब 15 फरवरी (रविवार) को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा की उपलब्धता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। उनकी फिटनेस को लेकर टीम और फैन्स दोनों ही चिंतित हैं।इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को लेकर विवादित बयान दे दिया है। पाकिस्तानी शो 'हारना मना है' में आमिर ने अभिषेक को 'स्लॉगर' बताया और कहा कि वह हर गेंद पर बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। आमिर ने कहा कि अभिषेक का खेल काफी हाई-रिस्क है, लेकिन अगर उनका दिन अच्छा रहे तो वे बड़ी पारी खेल सकते हैं। आमिर ने यह भी कहा कि उन्हें स्विंग गेंदबाजी और शरीर पर गेंद डालकर रोका जा सकता है।हालांकि आमिर ने अभिषेक की आलोचना की, लेकिन उन्होंने माना कि अगर अभिषेक लय में आते हैं, तो विपक्षी टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।फिलहाल, अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उपलब्धता और फिटनेस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अगर वे स्वस्थ होकर मैदान पर उतरते हैं, तो भारत के लिए यह बड़ा मैच-विनिंग कारक हो सकता है, जबकि पाकिस्तान को उनकी बल्लेबाजी के लिए सतर्क रहना होगा।

UAE ने कनाडा को 5 विकेट से हराया

UAE ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के 20वें मैच में कनाडा को 5 विकेट से हराया। टीम ने ग्रुप डी में पहली जीत हासिल की है। इसी के साथ अमीरात की टीम तीसरे नंबर पर आ गई है। दिल्ली में कनाडा ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। कनाडा ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 150 रन बनाए। जवाब में UAE ने 151 रन का टारगेट 19.4 ओवर में 5 विकेट पर चेज कर लिया। अर्यांश शर्मा ने नाबाद 74 और सोहैब खान ने 51 रन बनाए। साद बिन जफर ने 3 विकेट झटके। हर्ष ठाकेर (50 रन) ने फिफ्टी लगाई। नवनीत धालीवाल ने 34 और श्रेयस मोव्वा ने 21 रन का योगदान दिया। कनाडा की ओर से जुनैद सिद्दीकी ने 5 विकेट झटके। एक विकेट मुहम्मद जवादुल्लाह को मिला।

रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान होंगे

IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम ने ऑलराउंडर रियान पराग को टीम का अगला कप्तान नियुक्त किया है। यह फैसला संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में चले जाने के बाद लिया गया है। 2026 के लिए हुए IPL के मिनी ऑक्शन से पहले संजू सैमसन ट्रेड विंडो के जरिये सीएसके में चले गए थे। सीएसके ने इसके बदले रवींद्र जडेजा और सैम करन जैसे दो ऑलराउंडर राजस्थान रॉयल्स को दिया था।

24 साल के रियान पराग पिछले सात सीजन से राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। संजू सैमसन ने पिछले सीजन के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने भविष्य को देखते हुए पराग पर भरोसा जताया है। रियान पराग के लिए कप्तानी का अनुभव नया नहीं है। IPL 2025 के दौरान जब संजू सैमसन चोट की वजह से 8 मैचों से बाहर रहे थे, तब पराग ने ही टीम की कमान संभाली थी। हालांकि, उन 8 मैचों में टीम को सिर्फ 2 जीत मिली थी, लेकिन बतौर बल्लेबाज पराग ने प्रभावित किया था। उन्होंने कप्तानी के दौरान 38.57 की औसत से रन बनाए थे, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेली गई 95 रनों की पारी उनके करियर का बेस्ट स्कोर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक,राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगाकारा ने कप्तान के चुनाव के लिए कई खिलाड़ियों के इंटरव्यू लिए थे। लंबी बातचीत और लीडरशिप क्वालिटी को परखने के बाद रियान पराग के नाम पर मुहर लगाई गई। पराग के सामने चुनौती बड़ी होगी क्योंकि रॉयल्स का पिछला सीजन काफी खराब रहा था। 2025 में टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीत पाई थी और पॉइंट्स टेबल में नीचे से दूसरे नंबर पर रही थी।

लोग बोले- 'हम फिर क्यों करें पढ़ाई ?

ड्राई क्लीनर की कमाई 2.8 लाख रूपये महीना

वायरल पोस्ट में इस ड्राई क्लीनर की आमदनी का ज़िक्र किया गया, जिसके बाद भारत में पढ़ाई और कमाई को लेकर पुरानी बहस फिर शुरू हो गई. आज कॉलेज की फीस लगातार बढ़ रही है और अच्छी नौकरी पाना भी मुश्किल होता जा रहा है.

बड़ी संख्या में जेन Z और मिलेनियल्स उच्च शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं. (Photo: Pixabay)

जिस शहर में एमबीए और इंजीनियर महीनों नौकरी ढूंढ रहे हों, वहीं गली के कोने की एक ड्राई क्लीनिंग दुकान वाला महीने में लगभग 3 लाख रुपये से ज्यादा कमा रहा है. यह सुनकर अगर आपको भी झटका लगा, तो आप अकेले नहीं हैं. इस वायरल कहानी ने सोशल मीडिया पर एक पुराना लेकिन असहज सवाल फिर उछाल दिया है—क्या मेहनत और हुनर अब डिग्री से ज़्यादा कीमती हो गए हैं? यह बात सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है कि क्या ज्यादा कमाने के लिए डिग्री होना जरूरी है. चलिए जानते हैं. एक वायरल पोस्ट में इस ड्राई क्लीनर की आमदनी का ज़िक्र किया गया, जिसके बाद भारत में पढ़ाई और कमाई को लेकर पुरानी बहस फिर शुरू हो गई. आज कॉलेज की फीस लगातार बढ़ रही है और अच्छी नौकरी पाना भी मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में कई लोग देख रहे हैं कि छोटे कारोबार और हुनर वाले काम, डिग्री वाली नौकरियों से कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं. ⊙

मज़ाक के लिए बनाया वायरल AI बुफे ऐप

बेंगलुरु के एक टेक्निकल एक्सपर्ट ने दावा किया है कि उनके द्वारा बनाए गए एक मज़ेदार AI बुफे ऐप के वायरल होने के बाद उन्हें ऑनलाइन जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं. उनका कहना है कि कुछ धमकियां सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके परिवार को भी निशाना बना रही हैं. बेंगलुरु के रहने वाले पंकज नाम के इस टेक्नीशियन ने बताया कि यह ऐप उन्होंने सिर्फ एक हल्के-फुल्के वीकेंड प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया था. ⊙

बेंगलुरु के टैक्सी ड्राइवर की ईमानदारी वायरल

रात में ढूंढकर लौटाया पासपोर्ट-PR कार्ड

इंटरनेट इन दिनों बैंगलुरु के एक ईमानदार कैब ड्राइवर उत्तम की जमकर तारीफ कर रहा है. कनाडा में रहने वाले फाउंडर ग्लेन इवान ने सोशल मीडिया पर बताया कि कैसे उन्होंने गलती से अपना पासपोर्ट, PR कार्ड और वॉलेट वाला बैग कैब में छोड़ दिया, लेकिन उत्तम ने रातभर की मेहनत के बाद वह बैग ढूंढकर उनके परिवार को लौटा दिया. ग्लेन ने लिखा कि रात करीब 2:30 बजे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लौटने के बाद वह सीधे घर पहुंचे और थकान के कारण सो गए. ⊙

आगे भी प्रेग्नेंट होने की बात कही

चर्चा में 10 बच्चों की सिंगल मदर

10 बच्चों की अकेली मां ने अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बताया कि वह कैसे सभी की परवरिश कर रही है. उसकी जिंदगी का हर दिन एक नई चुनौती होती है. फिर भी वह आगे और बच्चे पैदा करना चाहती है. यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस महिला की कहानी काफी दिलचस्प है.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, साउथहैम्पटन की रहने वाली सोन्या ओ'लॉघलिन , एक सिंगल मां के रूप में अपने 10 बच्चों के साथ चार बेडरूम वाले काउंसिल हाउस में रहती हैं.मां को दिन-प्रतिदिन बहुत दबावों का सामना करना पड़ता है. इसमें परिवार चलाने के लिए वित्तीय प्रबंधन , रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी, अपने सभी बच्चों पर ध्यान देना और बच्चों की शैतानियों पर नजर रखना शामिल होता है. सोन्या की छह बेटियां और चार बेटे हैं. सभी बच्चों के नाम क्रम अनुसार निकोला, लीह, शैनन, केओन, एरिन, काई, काना, लुईस, लेक्सी और डैनियल हैं. यूट्यूब के ओरिजिन चैनल से अपनी दिनचर्या के बारे में बात करते हुए सोन्या ने कहा किदस बच्चों के साथ जीवन काफी व्यस्त होता है. बच्चे मुझे हमेशा सतर्क रखते हैं. उनका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है. जब वह सबको जगाती हैं और स्कूल के लिए तैयार करती है. उन्होंने कहा कि सुबह का समय मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है. क्योंति मुझे यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी अपना नाश्ता कर लें. ⊙

बॉक्स ऑफिस पर 'O Romeo' की मजबूत शुरुआत

सुबह के शोज में तालियों के बीच एडवांस बुकिंग भी अच्छी

शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी फिल्म 'ओ रोमियो' के साथ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुई इस रोमांटिक-एक्शन थ्रिलर को लेकर दर्शकों में खास उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले ही मजबूत रही है और सुबह के शोज में दर्शक तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं।विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी यह फिल्म शुक्रवार, 13 फरवरी को रिलीज हुई। वैलेंटाइन डे के माहौल का पूरा फायदा उठाने वाली इस फिल्म की एडवांस बुकिंग लगभग 3.05 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। शहरी इलाकों में फिल्म को विशेष तौर पर अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, कुल 12,344 शोज के लिए फिल्म के 1.18 लाख से अधिक टिकटों की प्री-बुकिंग हुई है। ब्लॉक सीटों को जोड़ने के बाद पहले दिन के लिए प्री-बुकिंग से कुल 5.90 करोड़ रुपये का ग्रॉस बिजनेस अनुमानित है।सुबह के शोज में लगभग 8-10 प्रतिशत सीटों पर दर्शक नजर आए और फिल्म की शुरुआत तालियों के साथ हुई। दिन बढ़ने के साथ ही दोपहर, शाम और रात के शोज में भीड़ बढ़ने की संभावना है। वैलेंटाइन डे का रोमांटिक माहौल फिल्म की कमाई में मदद करेगा। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, पहले दिन फिल्म की कमाई भले ही 10 करोड़ रुपये से कम रहे, लेकिन सप्ताहांत में कपल ऑडियंस और वर्ड ऑफ माउथ के दम पर यह फिल्म अच्छा कारोबार कर सकती है।

बॉक्स ऑफिस की प्रतिस्पर्धा

ओ रोमियो' की असल टक्कर इस समय 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' जैसी फिल्मों से है। हालांकि, ये दोनों फिल्में अब दर्शकों को खास आकर्षित नहीं कर पा रही हैं। सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने गुरुवार को 1.75 करोड़ रुपये, जबकि रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' ने 1.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। शुक्रवार को ही शनाया कपूर और आदर्श गौरव की 'तू या मैं' भी रिलीज हुई। बिजॉय नांबियार की इस फिल्म को आलोचकों से तारीफ मिली है, लेकिन कमाई में यह 'ओ रोमियो' से पीछे दिख रही है।शहरी इलाकों में फिल्म को खासतौर पर अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े बताते हैं कि दर्शक फिल्म के लिए उत्साहित हैं। ब्लॉक सीटों और प्री-बुकिंग को मिलाकर पहले दिन के लिए अनुमानित ग्रॉस बिजनेस लगभग 5.90 करोड़ रुपये है। यह आंकड़ा फिल्म की संभावित सफलता का संकेत देता है, खासकर वैलेंटाइन डे और सप्ताहांत के मौके पर।विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म का रोमांटिक और थ्रिलर तत्त्व, शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री, और विशाल भारद्वाज का निर्देशन दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचेगा। शनिवार और रविवार को कपल ऑडियंस और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना सकती है।इस तरह, 'ओ रोमियो' ने अपनी शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर मजबूत की है और आने वाले दिनों में इसके प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी।

सातवीं मंजिल से नीचे सरकती आई लिफ्ट, LDA उपाध्यक्ष समेत 7 अधिकारी सभी सुरक्षित

लखनऊ के सीजी सिटी स्थित सीएसआई टावर में निरीक्षण के दौरान एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार समेत सात अधिकारी लिफ्ट खराबी से फंस गए। लिफ्ट सातवीं मंजिल से नीचे आ गई, लेकिन सभी सुरक्षित रहे। घटना के बाद कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

राजधानी के सीजी सिटी स्थित सीएसआई टावर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। निरीक्षण के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार समेत सात अधिकारी लिफ्ट में सवार थे, तभी सातवीं मंजिल पर पहुंचते ही लिफ्ट अचानक झटके खाती हुई सरसराते हुए नीचे आ गई।गनीमत रही कि किसी अधिकारी को चोट नहीं आई, लेकिन कुछ देर तक सभी अधिकारी लिफ्ट के भीतर फंसे रहे। घटना के बाद टावर परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही इंजीनियर और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लिफ्ट का दरवाजा खोलकर सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।जानकारी के अनुसार, एलडीए द्वारा सीजी सिटी में आईएएस अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे 14-14 मंजिला दो टावरों का निरीक्षण करने उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। 'बी' ब्लॉक के निरीक्षण के लिए वे चीफ इंजीनियर मानवेंद्र सिंह, अधीक्षण अभियंता नवीनत कुमार शर्मा समेत अन्य अधिकारियों के साथ 14वीं मंजिल पर जा रहे थे।बताया गया कि लिफ्ट सातवीं मंजिल पर पहुंची ही थी कि अचानक उसमें तकनीकी खराबी आ गई। तेज झटकों और आवाज के साथ लिफ्ट नीचे की ओर आने लगी। कुछ ही सेकेंड में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक गई। हालांकि दरवाजा नहीं खुला और सभी अधिकारी अंदर फंसे रह गए।लिफ्ट के अचानक नीचे आने से मौजूद अधिकारियों में घबराहट फैल गई, लेकिन सभी ने संयम बनाए रखा। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद तकनीकी टीम सक्रिय हुई। कुछ समय बाद दरवाजा खोलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया।एलडीए द्वारा आईएएस अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे ये टावर करीब नौ वर्ष पहले 'सीएसआई टावर्स-2' परियोजना के तहत शुरू किए गए थे। बीच-बीच में निर्माण कार्य रुकने के बाद अब यह परियोजना फिनिशिंग स्टेज में पहुंची है। निरीक्षण के दौरान हुई इस घटना ने निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।घटना से नाराज उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने लिफ्ट लगाने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चीफ इंजीनियर को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। इसके बाद जोन-1 के इंजीनियर की ओर से सुशांत गोल्फ सिटी थाने में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ तहरीर दी गई।सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस तकनीकी पहलुओं की भी जांच करेगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लिफ्ट में खराबी किस कारण से आई।इस घटना के बाद एलडीए प्रशासन ने पूरे सीएसआई टावर के निर्माण कार्य की निगरानी और गुणवत्ता की जांच के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता को परियोजना की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इस हादसे ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों की अनिवार्यता को एक बार फिर रेखांकित किया है। हालांकि सभी अधिकारी सुरक्षित हैं, लेकिन घटना ने टावर परिसर में मौजूद लोगों को कुछ समय के लिए दहशत में डाल दिया। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि तकनीकी खराबी का वास्तविक कारण क्या था और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी।

वाटर टैंकर और ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक सवार की मौत, पुलिस ने वाहनों को जब्त किया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

महिंगवां थाना क्षेत्र के दरियापुर चौराहे पर एक भयानक सड़क हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना तब हुई जब एक वाटर टैंकर और ट्रैक्टर के साथ बाइक आमने-सामने टकरा गई।मौके पर ही हुई घटनास्थल की जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान मुसपिपरी निवासी प्रभात कुमार रावत उर्फ संजू (45) पुत्र राम प्रकाश रावत के रूप में हुई है। प्रभात के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। बाइक पर पीछे बैठे सुरेश चंद्र भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उपचार शुरू किया गया।घटना की सूचना मिलते ही महिंगवां थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों – वाटर टैंकर और ट्रैक्टर – को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दरियापुर चौराहे पर अक्सर तेज़ रफ्तार वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और राहगीरों और स्थानीय लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद की। महिंगवां थाना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमेशा यातायात नियमों का पालन करें और तेज़ रफ्तार वाहन चलाने से बचें। इस घटना ने फिर एक बार सड़क सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है और स्थानीय प्रशासन की सतर्कता की जरूरत को बढ़ा दिया है।घटना के दौरान मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों में गहरी शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

लखनऊ नगर निगम की बैठक में बजट तैयार

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

राजधानी के नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,278.34 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है, जिसमें शहर के विकास और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। गुरुवार को निगम मुख्यालय में हुई बैठक में इस बजट पर विस्तार से चर्चा हुई। राहत की बात यह है कि इस बार किसी नए कर या मौजूदा कर में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं रखा गया है।बजट में सबसे बड़ा प्रावधान कूड़ा प्रबंधन के लिए रखा गया है। नगर निगम ने इस मद के लिए करीब 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाना बताया गया है। वहीं, नालों की सफाई के लिए केवल 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो हर साल सवालों के घेरे में रहता है। बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से जूझ रहे इलाकों के लिए यह राशि कम नजर आती है।सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 326.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि यह राशि शहर के विस्तार और बढ़ते ट्रैफिक दबाव के अनुसार पर्याप्त नहीं है। सड़कों के निर्माण के लिए सीएम ग्रिड योजना के तहत अलग से 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बावजूद इसके, बड़े पैमाने पर सड़क सुधार की उम्मीद रखने वाले लोगों को बजट कुछ सीमित नजर आता है।नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती पुराने निर्माण कार्यों के भुगतान की है। इसके लिए बजट में 370 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। यह राशि उन परियोजनाओं के भुगतान के लिए है, जो पहले किए गए कार्यों के लिए लंबित हैं। वहीं, कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान की राशि में कटौती की गई है। पुनरीक्षित बजट में 130 करोड़ का प्रावधान था, जिसे घटाकर 100 करोड़ कर दिया गया है, जिससे ठेकेदारों और एजेंसियों में असंतोष पैदा होने की संभावना है।पार्कों, स्ट्रीट लाइट और भवनों पर खर्च बढ़ाया गया है। पार्कों के अनुरक्षण के लिए बजट 38.38 करोड़ से बढ़ाकर 42 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें रंगाई-पुताई के लिए 6 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मार्ग प्रकाश के लिए 16 करोड़, स्ट्रीट लाइट मरम्मत के लिए 6 करोड़ और उपकरण खरीद के लिए 6.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नए निर्माण कार्यों के लिए 7 करोड़, भवन मरम्मत के लिए 5 करोड़, फ्लैट निर्माण के लिए 25 करोड़ और अहाना एनक्लेव की बहुमंजिली आवासीय योजना के लिए 40 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।इस बार भूमि सर्वे और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए पहली बार बड़ा प्रावधान किया गया है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि पहले यह राशि केवल 4 करोड़ थी। इसे अवैध कब्जों पर रोक लगाने के महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। शहरी निर्धनों के लिए भी 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।अवस्थापना निधि से 180 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा, मॉडल वेंडिंग जोन के निर्माण और संचालन का बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया है।प्रस्तावित बजट को फरवरी के अंतिम सप्ताह में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में रखा जाएगा, जहां इसे अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नगर निगम के इस बजट से राजधानी के विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी दिख रही है, हालांकि कुछ मदों में राशि सीमित होने के कारण चुनौतियां भी बरकरार हैं।

लखनऊ में 6 को रौंदने वाला गौरव सिंह गिरफ्तार

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में स्विफ्ट डिजायर कार से गाड़ियों में टक्कर मारते हुए 6 लोगों को रौंदने वाला 12वीं का स्टूडेंट गौरव सिंह गिरफ्तार हो गया है। इस हिट एंड रन की CCTV फुटेज भी सामने आई है। इस हादसे में एक 6 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी। 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतक बच्चे की पहचान उन्नाव की साधना के बेटे दीक्षांत के रूप में हुई है। वह नानी के साथ पहली बार बाजार आया था। सूचना मिलने पर उसकी मां अस्पताल पहुंची और बेटे के शव से कफन हटाते ही चीख पड़ी। हादसे के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे एक घंटे के भीतर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था। कार में उसकी एक क्लासमेट भी मौजूद थी, जो दुर्घटना के बाद वहीं उतर गई। स्थानीय लोगों ने लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह हादसा गुरुवार शाम करीब 7 बजे बंथरा थाना क्षेत्र में कानपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास हुआ। कार

रुकते ही लड़की उतर गई, जबकि छात्र कार लेकर भाग निकला। एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा के अनुसार, पुलिस ने कार को ट्रेस कर आरोपी छात्र गौरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया और कार भी जब्त कर ली है। गौरव की कार बेकाबू थी। वह अवध कॉलेजिएट में 12वीं में पढ़ता है। वह और उसकी क्लासमेट मोहन रोड स्थित एक फेयरवेल पार्टी से लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने कार से उतारी गई लड़की से पूछताछ कर CCTV फुटेज के सहारे कार चालक का पता लगाने लगी। महज एक घंटे में उसकी कार ट्रेस कर ली। पुलिस ने ड्राइवर गौरव को गिरफ्तार कर पूछताछ की। बंथरा प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश सिंह ने बताया- दोनों लड़के-लड़की अवध कॉलेजिएट के स्टूडेंट हैं।

लखनऊ में चलती कार में लगी भीषण आग

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ-सीतापुर हाईवे पर गुरुवार देर रात एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार खदरा निवासी डॉक्टर चंद्रप्रकाश का परिवार लखनऊ से सीतापुर एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था।

बताया गया कि रास्ते में गाड़ी के ओवरहीट होने की सूचना पर चालक ने कार को सड़क किनारे रोका। इसी दौरान अचानक कार में आग लग गई और देखते ही देखते क्विड कार जलने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही बक्शी का तालाब थाना क्षेत्र की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। इस हादसे में डॉक्टर चंद्रप्रकाश और उनका परिवार बाल-बाल बच गया। समय रहते सभी लोग कार से बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन:

पुलिस ने धक्का-मुक्की कर गाड़ियों में ठूंसा

लखनऊ विश्वविद्यालय पर UGC के समर्थन में शुक्रवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने जोरदार हंगामा किया। छात्रों की कोशिश 'समता संवर्धन मार्च' निकालने की थी। पुलिस बल ने उन्हें रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। प्रदर्शन शुरू होता कि उससे पहले पुलिस ने सभी छात्रों को घेर लिया। इस दौरान छात्र जमीन पर बैठ गए। पुलिस ने घसीट-घसीटकर गाड़ी में डाल दिया। इस दौरान एक छात्र ऐसा भी था जिसे पुलिस गाड़ी के अंदर डाल रही थी लेकिन वह चिल्ला रहा था- 'मैं धरने में नहीं हूं। मैं धरना नहीं कर रहा हूं।' कुछ देर बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। वह गाड़ी से किसी तरह उतरकर दूर जाकर खड़ा हो गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे छात्र और पुलिसकर्मियों में लगातार नोकझोंक हुई। पुलिस ने छात्रों को प्रदर्शन से रोका। उन्हें गेट से बाहर निकलने नहीं दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र जमीन पर ही बैठ गए। छात्रों की संख्या अधिक होने के चलते RRF ने भी मोर्चा संभाला। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि जब तक UGC लागू नहीं करवा लेंगे, पीछे नहीं हटने वाले। लखनऊ यूनिवर्सिटी में UGC के समर्थन के प्रदर्शन में समाजवादी छात्र सभा, आईसा, एनएसयूआई, एससीएस, बीएएसएफ, एसएफआई, बाप्सा, युवा और अंबेडकरवादी विद्यार्थी संघ समेत लगभग एक दर्जन छात्र संगठन शामिल हुए। छात्र राणा सुधांशु ने कहा- हम लोगों का प्रदर्शन UGC के उन नए नियमों के समर्थन में है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मेरा कहना है कि नए नियमों से इतना डरना क्यों? जब आप एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों से भेदभाव नहीं करते हो तो डरते क्यों हो? उनको अपने साथ बैठाते हो, किसी तरह से अपमानित नहीं करते तो फिर UGC के नए नियमों से डर क्यों रहे हो? यह नियम हमें समानता से रहने का मौका देगा। प्रदर्शन में शामिल तेजपाल ने कहा कि UGC इसलिए जरूरी है क्योंकि 2018 से 21 तक में एससी-एसटी और ओबीसी के 98 छात्रों की मौत हुई। रोहित वेमुला जैसे छात्रों की मौत इस बात का उदाहरण है

कि यूनिवर्सिटी में कितना भेदभाव है। एम्स के पड़ोस में एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर जातिगत आधार पर 30 से अधिक छात्रों के नंबर काटकर फेल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमेटी बनी और आगे छात्रों के हित में फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2013 के यूजीसी बिल से काम नहीं चल पा रहा है इसलिए नया कानून लाया जा रहा है। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया।

गंगा बैराज पर जाम को लेकर अखिलेश यादव का हमला

बोले– '45 मिनट' के दावे में 90 मिनट का जाम भी शामिल है क्या?

टीवी भारतवर्ष उत्तर प्रदेश

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ से कानपुर जाते समय गंगा बैराज पर लगे भीषण जाम का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें लखनऊ से कानपुर की दूरी 45 मिनट में तय कराने की बात कही जाती है।अखिलेश यादव ने X पर लिखा, "दावा तो ये है कि लखनऊ से कानपुर 45 मिनट में पहुंचा देंगे, 'उल्टी गणितवालों' से सब पूछ रहे हैं कि दो स्मार्ट सिटी के बीच में ये जो गंगा ब्रिज पर 90 मिनट का जाम लगता है, वो इसमें शामिल है या अनुपूरक बजट की तरह इसकी बात अलग से की जाएगी। भाजपाइयों की यही सबसे बुरी बात है कि जितना बताते नहीं हैं, उससे दोगुना छिपाते हैं।"गंगा बैराज पर लगभग 90 मिनट तक जाम में फंसे रहने के बाद सपा प्रमुख कानपुर के जाजमऊ पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे।जाजमऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के हितों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और सपा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में अंतर साफ दिखाई देता है। उन्होंने गंगा बैराज पर लगे जाम का उदाहरण देते हुए कहा कि बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन आम जनता को रोजमर्रा की समस्याओं से जूझना पड़ता है।जाजमऊ कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव मेहरबान सिंह के पुरवा में रिटायर्ड जज श्याम सिंह यादव के आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद वे जिला अध्यक्ष फजल महमूद के पुत्र सैय्यद मोहम्मद अहमद के विवाह समारोह से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है। सैय्यद मोहम्मद अहमद का विवाह 7 फरवरी को संपन्न हुआ है।वर-वधू को आशीर्वाद देने के लिए अखिलेश यादव आज सिविल लाइन स्थित उनके निवास स्थान पहुंचेंगे। वहां आशीर्वाद देने के बाद वे आर्यनगर से विधायक अमिताभ बाजपेई के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए बिठूर के लिए रवाना होंगे।सपा प्रमुख के इस दौरे को राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के मिश्रण के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर उन्होंने गंगा बैराज के जाम को लेकर सरकार पर हमला बोला, वहीं दूसरी ओर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावों की तैयारियों पर जोर दिया।गंगा बैराज पर लगे जाम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थकों और विपक्षी दलों के बीच इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव के बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में भी बहस तेज हो गई है।इस पूरे घटनाक्रम के बीच सपा प्रमुख ने यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी जनता के मुद्दों को उठाने में पीछे नहीं हटेगी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की अपील की।लखनऊ से कानपुर की यात्रा के दौरान गंगा बैराज पर जाम की घटना ने एक बार फिर यातायात व्यवस्था और शहरी बुनियादी ढांचे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।

काशी में महाशिवरात्रि से पहले बाबा विश्वनाथ की हल्दी यात्रा की शुरुआत 13 फरवरी से

टीवी भारतवर्ष वाराणसी

महाशिवरात्रि से पूर्व काशी में बाबा विश्वनाथ के शिव विवाह की रस्मों की औपचारिक शुरुआत 13 फरवरी को होगी। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ को सगुन की हल्दी लगाई जाएगी। हल्दी की पारंपरिक यात्रा शीतला मंदिर के महंत पं. शिवप्रसाद पांडेय 'लिंगिया महाराज' के बांसफाटक स्थित आवास से टेढ़ीनीम स्थित पूर्व महंत आवास के लिए प्रस्थान करेगी। यहां बाबा की पंचबदन चल प्रतिमा पर हल्दी अर्पित की जाएगी।शीतला मंदिर के उपमहंत अवशेष पांडेय 'कल्लू महाराज' ने बताया कि काशी की लोकपरंपरा के अनुसार शिव विवाह से पूर्व बाबा को सगुन की हल्दी चढ़ाई जाती है। महंत परिवार द्वारा विशेष रूप से नासिक से हल्दी मंगाई गई है। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है और काशीवासियों के लिए इसका विशेष धार्मिक महत्व है।सारंगनाथ सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ के अध्यक्ष राहुल सिन्हा और मंत्री टिप्पु पांडेय ने बताया कि बाबा के ससुराल सारंगनाथ मंदिर से ससुरालीजन भी हल्दी लेकर लिंगिया महाराज के आवास पर महंत मनीष उपाध्याय के सानिध्य में पहुंचेंगे। इस दौरान हल्दी यात्रा के साथ विभिन्न धार्मिक रस्में निभाई जाएंगी, जो काशी की पारंपरिक संस्कृति और लोकमान्यताओं को दर्शाती हैं।शिव बारात समिति के महामंत्री दिलीप सिंह ने बताया कि समिति के सदस्य और काशीवासी बांसफाटक स्थित पूर्व महंत आवास पर एकत्र होकर यात्रा के रूप में आगे बढ़ेंगे। इस यात्रा में भाग लेने वाले लोग बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करेंगे। यह उत्सव न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काशीवासियों के लिए विशेष अनुभव बनाता है।पूर्व महंत परिवार के प्रतिनिधि पं. वाचस्पति तिवारी ने बताया कि हल्दी चढ़ाने से पूर्व परिवार की वरिष्ठ सदस्य मोहिनी देवी के सानिध्य में पं. सुशील त्रिपाठी के आचार्यत्व में 11 वैदिक बाबा की पंचबदन प्रतिमा का विशेष पूजन किया जाएगा। यह पूजन बाबा विश्वनाथ के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है और इसे धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा माना जाता है।महाशिवरात्रि के इस अवसर पर हल्दी यात्रा का आयोजन न केवल पारंपरिक धार्मिक रस्मों को बनाए रखने का माध्यम है, बल्कि यह काशीवासियों और श्रद्धालुओं को एकजुट करने का अवसर भी प्रदान करता है। हल्दी यात्रा में भाग लेने वाले भक्त और श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हुए धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे।इस प्रकार काशी में महाशिवरात्रि से पूर्व बाबा विश्वनाथ के शिव विवाह की रस्मों की शुरूआत 13 फरवरी से हो रही है। हल्दी यात्रा, पंचबदन प्रतिमा पर हल्दी अर्पित करना, वैदिक पूजन और ससुरालीजनों का आगमन सभी मिलकर इस धार्मिक परंपरा को जीवंत बनाएंगे। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि काशी की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे एक जीवंत परंपरा के रूप में प्रस्तुत करता है।इस वर्ष भी बाबा विश्वनाथ के शिव विवाह की रस्में काशीवासियों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी, और धार्मिक आस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक आयोजनों की महिमा को प्रदर्शित करेंगी।

उन्नाव में मनरेगा बचाने को कांग्रेस की 15 किमी पदयात्रा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में शुक्रवार को "मनरेगा बचाओ संग्राम पदयात्रा" का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र से शुरू होकर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसभा के साथ संपन्न हुई। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, ग्रामीण मजदूर और पार्टी समर्थक शामिल हुए, जिन्होंने योजना के समर्थन और केंद्र सरकार के विरुद्ध अपना विरोध जताया।जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह पदयात्रा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक जिले में आयोजित की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा योजना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और उसकी जगह नई योजना लागू करने की तैयारी में है। कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस कदम का विरोध कर रही है और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए जमीनी स्तर पर आंदोलन जारी रखेगी।उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों, मजदूरों और युवाओं के अधिकारों का लगातार हनन कर रही है। कुशवाहा ने बताया कि मनरेगा योजना ग्रामीण मजदूरों के लिए 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करती है और यह योजना गांवों में जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करती है। यदि इस योजना को समाप्त किया जाता है या इसके स्वरूप में बदलाव होता है, तो ग्रामीण मजदूरों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस ने इस पदयात्रा के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाया।जनसभा में पार्टी के अन्य नेताओं ने भी मनरेगा योजना और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण आधार है। नेताओं ने जनता को आश्वस्त किया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार को पूर्व में किसान कानून वापस लेने पड़े थे, उसी तरह जनदबाव के माध्यम से मनरेगा को मजबूती के साथ लागू कराया जाएगा।रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर जोरदार नारेबाजी की। उनके नारों में मनरेगा योजना को यथावत रखने, ग्रामीण रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में चेतावनी देने का संदेश स्पष्ट रूप से देखा गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित सभा में उपस्थित नेताओं ने कहा कि सरकार को ग्रामीण मजदूरों और किसान समुदाय के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।कार्यक्रम के अंत में सुरेंद्र कुशवाहा और अन्य नेताओं ने संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने और आगामी दिनों में आंदोलन को और तेज करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर जनता के साथ खड़ी रहेगी और मनरेगा योजना के समर्थन में निरंतर अभियान चलाती रहेगी।पदयात्रा और जनसभा ने यह संदेश दिया कि ग्रामीण रोजगार और मजदूर अधिकार कांग्रेस के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। इस आयोजन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीण समुदाय को एकजुट किया और मनरेगा योजना के महत्व और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई।इस प्रकार सुरेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में "मनरेगा बचाओ संग्राम पदयात्रा" ने ग्रामीण मजदूरों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह और एकजुटता का नया संचार पैदा किया, जिससे आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और मजबूती मिलने की संभावना है।

कानपुर में आस्था सिंह की तहरीर पर पुलिस ने शुरू की जांच, ऋतु के पति से 20 मिनट पूछताछ

टीवी भारतवर्ष कानपुर

कानपुर के HDFC बैंक में 'मैं ठाकुर हूं' कहने वाली कर्मचारी का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में आस्था सिंह भदौरिया और ऋतु त्रिपाठी ने पनकी थाने में अलग-अलग तहरीर दी थी। आस्था ने पूर्व बैंककर्मी ऋतु त्रिपाठी, उनके पति और ननद के खिलाफ वीडियो वायरल करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। जबकि ऋतु ने धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को पुलिस ने ऋतु के पति ऋषि त्रिपाठी से करीब 20 मिनट तक पूछताछ की। पति ने वीडियो वायरल करने से इनकार किया है। पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह ने बताया-

आस्था सिंह और ऋतु त्रिपाठी के मामले की जांच की जा रही है। बैंक बीते तीन दिनों से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इस वजह से जांच अटकी हुई है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारों से पहले प्रशासन सतर्क

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में आगामी महाशिवरात्रि, रमजान और होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में सदर कोतवाली और गंगाघाट थाना क्षेत्र में पीस कमेटी की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में अधिकारियों ने धर्मगुरुओं, संभ्रांत नागरिकों और कार्यक्रम आयोजकों के साथ संवाद कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज, उपजिलाधिकारी सदर क्षितिज द्विवेदी और क्षेत्राधिकारी नगर बिनी सिंह उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सभी से त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ शिकायत करने वाले को धमकी

टीवी भारतवर्ष वाराणसी

जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाया। 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में वाद (शिकायत) दायर किया। अब वाद दायर करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज को धमकी मिली है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने प्रयागराज पुलिस के अधिकारियों को एप्लिकेशन भेजकर धमकी देने, वाहन में आग लगवा देने, कोर्ट में पेश होने वाले नाबालिगों को मरवा देने की धमकी का आरोप लगाया है।

उनका कहना है कि फोन कर धमकी दी गई। इसके बाद वॉट्सऐप कॉल पर भी धमकाया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि 11 फरवरी 2026 की रात लगभग 9.16 बजे कॉल आई। इसमें कोर्ट में उपस्थित होने पर वाहन में आग लगवाने की धमकी दी गई।

नाबालिग पीड़ित बालक की हत्या कराए जाने की धमकी दी गई, लंबित शिकायतें वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। इसके बाद उसी नंबर से रात 9.29 और 9.31 बजे वॉट्सऐप पर वीडियो और वॉइस कॉल आई। वीडियो कॉल में हथियार जैसा कुछ दिखा कर डराया गया। अश्लील और आपत्तिजनक शब्द बोले। नाबालिग बालक के संबंध में अभद्र टिप्पणियां की गईं। नग्न होकर अश्लीलता की गई। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज के इन आरोपों और पुलिस की कार्रवाई को लेकर कोई भी पुलिस अफसर इस पर बोलने को तैयार नहीं है।

नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में शामिल होने की अटकलें तेज, 15 फरवरी को ज्वाइनिंग की चर्चा

पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के 15 फरवरी को अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा है। कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके अगले कदम पर कयास थे। उनके सपा में आने से पार्टी को बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में राजनीतिक मजबूती मिल सकती है।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने की चर्चा है। बहुजन समाज पार्टी सरकार में 'मिनी सीएम' कहे जाने वाले और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी का दामन थामने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 15 फरवरी को अखिलेश यादव की मौजूदगी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी औपचारिक रूप से सपा में शामिल हो सकते हैं।हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अगले राजनीतिक कदम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। चर्चा यह भी थी कि वह चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ जाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 'दलित-मुस्लिम' गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि अब संकेत मिल रहे हैं कि उनका अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी हो सकता है।नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ पूर्व मंत्री अनीस अहमद (फूल बाबू) के भी सपा में शामिल होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले संगठनात्मक मजबूती मिल सकती है।नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में यूपी Tak के एक पॉडकास्ट में भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर संकेत दिए थे। जब उनसे सपा में जाने के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, "अखिलेश जी अभी दिल्ली में संसद सत्र में व्यस्त हैं। उनके लखनऊ आने पर बात होगी। हर बात अभी कहलवा लेंगे तो अगली बार के लिए क्या बचेगा?" उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई थीं।इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि उनके पुराने साथी जैसे बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा और इंद्रजीत सरोज पहले से ही समाजवादी पार्टी में हैं, जो उनके फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। यह बयान भी सपा में संभावित शामिल होने के संकेत के रूप में देखा गया।विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता के पार्टी में आने से सपा को बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के साथ-साथ बसपा के कैडर वोट में भी सेंधमारी करने में मदद मिल सकती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी कांशीराम के करीबी माने जाते थे और मायावती सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में उनकी गिनती होती थी। बसपा सरकार में उन्हें 'मिनी सीएम' कहा जाता था। हालांकि उनका राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है।भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की बेटी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद वह लंबे समय तक चर्चा और विवादों में रहे। बाद में मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सतीश चंद्र मिश्रा पर साजिश के आरोप लगाए थे।बसपा से अलग होने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन वहां भी उनका राजनीतिक सफर लंबा नहीं चल पाया। अब बसपा और कांग्रेस का सफर तय करने के बाद उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।यदि 15 फरवरी को उनकी सपा में औपचारिक एंट्री होती है तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें इस संभावित ज्वाइनिंग पर टिकी हुई हैं, जो आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक दिशा पर असर डाल सकती है।

टॉयलेट का विरोध किया तो सिपाही ने मार डाला

टीवी भारतवर्ष प्रयागराज

प्रयागराज में शादी समारोह में युवक की हत्या कर दी गई। वजह यह थी कि उसने खाली प्लॉट में पेशाब करने का विरोध किया। आरोप है कि इस पर सिपाही भड़क गया। फिर उसने साथियों के साथ चापड़ और तंदूर बनाने वाली लोहे की सरिया से हमला कर दिया। युवक पर 6-7 वार किए गए। वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में उसकी जान चली गई। वारदात के बाद आरोपी भाग गए। युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। गेस्ट हाउस में तोड़-फोड़ की।

शव सड़क पर रखकर बैठ गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और भीड़ को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे। हालांकि, बाद में अफसरों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। मुख्य आरोपी सिपाही का नाम सुनील कनौजिया है। उसकी ताऊ की बेटी की शादी थी। मृतक की पहचान राजेश निषाद के रूप में हुई। घटनास्थल से 100 मीटर दूर ही उसका घर है। मामले में पुलिस ने सुनील कनौजिया समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरी घटना गुरुवार रात नैनी थाना क्षेत्र के कुशवाहा गेस्ट हाउस के सामने हुई। मड़ौका के रहने वाले ननकऊ की बेटी की शादी गुरुवार को थी। बारात कुशवाहा गेस्ट हाउस में आई थी। देर रात 12 बजे बाराती खाना-पीना और नाच-गाना कर रहे थे। इसी दौरान कुछ बाराती पास में रहने वाले राजेश निषाद के खाली पड़े प्लॉट में पेशाब करने चले गए। उसी प्लॉट में राजेश की गाड़ी खड़ी थी। राजेश ने गाड़ी के पास पेशाब करने का विरोध किया। इस पर कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि बात बढ़ने पर गाली-गलौज और फिर मारपीट होने लगी। इसी बीच ननकऊ का भतीजा सुनील कनौजिया भी वहां पहुंच गया।

मुख्तार के शूटर शोएब की दिनदहाड़े हत्या

टीवी भारतवर्ष बाराबंकी

मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब किदवई उर्फ बॉबी की शुक्रवार दोपहर बाराबंकी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार, शोएब लखनऊ से बाराबंकी जा रहा था। जैसे ही वह हाईवे पर 100 मीटर आगे बढ़े, दो बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उनकी कार पर पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शोएब पर 25 से अधिक गोलियां चलाई गईं। गोली लगने के बाद वह घायल होकर कार में ही गिर पड़े। हमलावरों ने वारदात को अयोध्या की तरफ फरार होकर अंजाम दिया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल शोएब को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।घटना कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ–अयोध्या हाईवे पर असेनी मोड़ के पास हुई। पुलिस ने बताया कि कार पर गोलियों के कई निशान हैं, जो वारदात की भयावहता को दर्शाते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल क्षेत्र को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया।पुलिस के अनुसार, यह हत्या पहले से सुनियोजित लगती है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान और उनके फरार होने का मार्ग पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि शूटिंग के पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं है।स्थानीय लोगों का कहना है कि बाराबंकी और आसपास के हाईवे पर यह वारदात चिंता का विषय है, क्योंकि सार्वजनिक जगह पर इतनी गोलियां चलाना सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। पुलिस ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखकर तुरंत सूचना दें। शोएब किदवई की हत्या ने बाराबंकी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों को पकड़ने का दावा किया गया है। इस घटना से माफिया गिरोहों के बीच जारी संघर्ष और स्थानीय कानून-व्यवस्था की स्थिति फिर से चर्चा में आ गई है।बाराबंकी पुलिस की फॉरेंसिक टीम और अन्य जांच अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद हैं और पूरी तरह से सबूत जुटाने में जुटे हुए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने गुस्से में फेंका हेडफोन

टीवी भारतवर्ष वाराणसी

यूपी विधानमंडल में बजट सत्र का आज 5वां दिन था और सदन में शुरुआत होते ही हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। भाजपा विधायक केतकी सिंह के टोके-टोके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भड़क गए। उन्होंने कहा, "आप बैठिए। सदन चलाना मेरा काम है।" इस दौरान गुस्से में उन्होंने हेडफोन निकालकर फेंक दिया। सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर कुर्सी से उठकर चले गए।सदन पुनः शुरू होने पर माहौल थोड़ा शांत हुआ। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने अध्यक्ष महाना से कहा कि "आप मुस्कुराते अच्छे लगते हैं।" इसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री से महाना को मनाने के लिए शायरी सुनाने की अपील की। इसी बीच सपा के कमाल अख्तर ने शायरी सुनाई – "तुम रूठा न करो, सबकी जान चली जाती है। तुम हंसते रहते हो, तो बिजली-सी चमक जाती है।" इस पर वित्त मंत्री ने हंसते हुए कहा कि "एक बात सुन लो, महबूबा वाली शायरी यहां न सुनाया करो।" इसके बाद वित्त मंत्री ने स्वयं शायरी प्रस्तुत की और सदन में हल्का माहौल बन गया।सत्र में महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित (रेगुलर) नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके साथ मनमानी न हो और उन्हें सुरक्षा और व्यवस्था मिले, इसलिए उनके लिए अलग से निगम बनाया गया है।सत्र के दौरान हंगामा और शायरी के बीच सदन में कई मुद्दों पर चर्चा जारी रही। अधिकारियों और विधायकों ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा, नियमितीकरण की संभावना और उनके हितों की रक्षा पर जोर दिया। सदन में यह भी देखा गया कि राजनीतिक दलों के बीच हल्की नोक-झोंक और हास्यपूर्ण माहौल दोनों देखने को मिला।इस घटना ने यह दर्शाया कि बजट सत्र में मुद्दों के अलावा सदन का वातावरण कभी-कभी अप्रत्याशित रूप ले लेता है। अध्यक्ष का गुस्सा और सदन स्थगित होना इस सत्र की चर्चा का मुख्य बिंदु बना। वहीं विधायकों की शायरी और हल्की नोक-झोंक ने सदन में माहौल को नियंत्रित करने का काम किया।सत्र के अंत तक यह स्पष्ट था कि अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन पर अपनी पकड़ कायम रखी और सदन में अनुशासन बनाए रखने का प्रयास किया। साथ ही, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम के गठन की जानकारी ने इस सत्र में एक ठोस प्रशासनिक पहल के रूप में विधायकों और जनता का ध्यान आकर्षित किया।